Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 10 | ISSUE : 6 | JUNE 2024

सतत विकास में नाबार्ड की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. कांता चौधरी [1] | मंजू कंवर [2]

[1] सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर.

[2] शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर.

ABSTRACT:

-

KEYWORDS:

-

PAPER ACCEPTED DATE:	PAPER PUBLISHED DATE:
29th June 2024	30th June 2024

प्रस्तावना

भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, हम सभी चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संकट न हो. हम किसी ढर्रे पर चलकर सुरक्षित भविष्य हासिल नहीं कर सकते. इसके लिए भौतिक आस्तियों, संरक्षण कार्यों, संस्थानों और मानव संसाधन में व्यापक निवेश की आवश्यकता है. साथ ही, हमें ऐसी संस्कृति विकसित करनी है जिसमें विभिन्न समुदायों के परस्पर विरोधी हितों की रक्षा करते हुए धरती माता की रक्षा के लिए सर्वोत्तम उपाय किए जा सकें।

पिछले कुछ दशकों में, जैसे–जैसे जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव, जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि और उसकी वजह से खाद्य सुरक्षा के खतरे हमारे सामने आ रहे हैं, वैसे–वैसे जलवायु परिवर्तन के संबंध में हमारी समझ बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन, जिसमें अत्यंत प्रतिकूल घटनाओं की भयावहता और बारंबारता बढ़ना शामिल है, ने खाद्य सुरक्षा और जल उपलब्धता पर प्रश्नचिह्न खड़े किए हैं और संधारणीय विकास के लक्ष्यों की कठिनता बढ़ाई हैं। हालांकि कृषि उत्पादकता में सकल रूप से वृद्धि हुई है, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से पिछले 50 वर्षों में वैश्विक रूप से इस वृद्धि की रफ्तार धीमी हुई है।

अध्ययन का उद्देश्य –

प्रस्तुत अध्ययन नाबार्ड द्वारा सतत विकास के लिए किए गए प्रयासों का विष्लेशण किया गया है जिसमें अध्ययन के निम्न उद्देष्य है–

1. नाबार्ड द्वारा भारतीय अर्थतंत्र के सतत विकास के लिए किए गए प्रयासों को समझना।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था में सतत विकास एवं नाबार्ड वित पोशित परियोजनाओं का विष्लेशण करना।
3. नाबार्ड की वित पोशित परियोजनाओं की समस्याओं को समझना तथा समाधान करने के उपाय ढुढना।

नाबार्ड मृदा व जल संरक्षण, जनभागीदारी के माध्यम से वाटरशेड विकास कार्यक्रमों, जल प्रयोक्ता संघों, खेत–तालाबों, भूमिगत जल–भरण, वाडी कार्यक्रमों, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं आदि के माध्यम से संधारणीयता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। नाबार्ड कृषि क्षेत्र में कृषि –प्रौद्योगिकी, मूल्य श्रृंखला प्रबंधन और प्राकृतिक कृषि प्रणालियों के माध्यम से संधारणीय आजीविका के समाधान प्रदान कर रहा है। इस अध्ययन में सुरक्षित भविष्य के लिए नाबार्ड द्वारा सतत विकास के किए गए कार्यों का विष्लेशण किया गया है.

1. जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान

वैश्विक और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए नाबार्ड अनेक उपाय कर रहा है जिनमें संकल्पना करना, सहयोग करना, निधि उपलब्ध कराना और विभिन्न गतिविधियों का संवर्धन शामिल है.

चित्र 1. नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन परियोजनाओं के लिए निधीया (राशि करोड़ में)

परियोजनाएं निधि वार	मंजूर	संवितरण
अनुकूलन निधि – 8	60.9	43.8
जलवायु परिवर्तन के लिए राश्ट्रीय अनुकलन निधि– 30	847.5	519.2
ग्रीन क्लाइमेट फंड – 2	944.2	402.4
जलवायु परिवर्तन निधि –	–	5.2
कुल 40 वार परियोजना	1852.6	970.6

स्त्रोत– नाबार्ड वार्शिक रिपोर्ट 2022–23

विभिन्न जलवायु निधियों के समन्वयक के रूप में नाबार्ड ने 40 परियोजनाओं के लिए कुल ₹1,852.6 करोड़ की ऋण व अनुदान सहायता का मार्ग प्रशस्त किया है। ये परियोजनाएँ विकास के नए आयाम तय कर रही हैं जिनसे भविष्य में सतत कृषि और पशुपालन को सहायता देकर और जलाऊ लकड़ी का उपयोग घटाकर पानी, कृषि भूमि और लघु वन उपज (एमएफ़पी) जैसे प्राकृतिक संसाधनों की अधिकतम उपलब्धता सुलभ की जा सकेगी.

जलवायु परिवर्तन के संबंध में नाबार्ड के कुछ प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं–

नाबार्ड द्वारा शुरू किए गए प्रमुख जलवायु–अनुकूल वित्तीय सेवा कार्यों का प्रभाव प्रदर्शित किया।

अनुकूलन और राहत उपायों को बढ़ावा देने के लिए कृषि व एसएमई क्षेत्र हेतु बेहतर वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता पर बल दिया।

जलवायु परिवर्तन केंद्र, बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान, लखनऊ द्वारा प्रशिक्षण व क्षमता–निर्माण।

वैश्विक संधारणीय विकास सम्मेलन, वैश्विक जल सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता से संबंधित क्षेत्रीय सम्मेलनोंध्संगोष्ठियों आदि को प्रायोजित किया।

कृषि विज्ञान केंद्र, दिल्ली में सोलर मांडल फार्म का निर्माण।

सिक्किम में ई–कचरा प्रबंधन के अध्ययन के लिए सहायता; और

मेंग्रोव, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, और गोवा में आजीविका अवसरों के संबंध में जागरूकता के प्रयास किए गए।

नाबार्ड ने अपनी विशिष्ट स्थिति का लाभ उठाते हुए ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि से नवीकरणीय ऊर्जा व जलवायु–स्मार्ट सिंचाई परियोजनाओं का वित्तपोषण करके अनेक अवसर सृजित किए हैं.

2. वाटरशेड विकास के लिए सहायता

नाबार्ड के सहभागितामूलक वाटरशेड परियोजनाएँ 1990 के दशक से वर्षा–सिंचित कृषि प्रणालियों में किसानों के आय अर्जन के जोखिम को कम करने के लिए प्रयासरत हैं. वित्तीय वर्ष 2022 में 1.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लागू होने वाली 156 नई परियोजनाएँ मंजूर की गईं और ₹.09.5 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2021 में ₹101.4 करोड़) की राशि संवितरित की गई। इसमें 31 स्प्रिंगशेड विकास और 48 केएफडब्ल्यू 12 मृदा परियोजनाएँ भी शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2022 की समाप्ति तक 28 राज्यों के 25.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तारित 3,557 परियोजनाएँ मंजूर की गई जिनके तहत कुल ₹2,014.3 करोड़ की राशि संवितरित की गई। इन प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजनाओं से मृदा व नमी संरक्षण, उच्च उत्पादकता, जलवायु सुरक्षा के साथ–साथ वर्तमान आजीविकाओं की सुरक्षा व निरंतरता सुनिश्चित करते हुए वैकल्पिक आजीविका अवसर भी प्रदान किए गए हैं।

- वित्तीय वर्ष 2022 में वाटरशेड और मृदा गुणवत्ता गतिविधियाँ

क्षारीय मृदा के पुनरुद्धार की प्रायोगिक परियोजना केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल के सहयोग से पंजाब व हरियाणा में प्रायोगिक परियोजना संचालित की गई. इस परियोजना से 2022 खरीफ सीज़न के दौरान करीब 2,000 हेक्टेयर क्षारीय भूमि का उपचार किया जाएगा। संधारणीय कृषि और संधारणीय जलचर पालन के लिए क्षमता वर्धन इस पहल के तहत, तेलंगाना व ओडिशा क्षेत्रीय कार्यालयों में दो ज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है।

परियोजना सहायक एजेंसियों के लिए इन केंद्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और 2,502 वाटरशेड परियोजनाएँ, 495 जनजाति विकास निधि परियोजनाएँ 8,185 कृषक–उत्पादक संगठन, 3,110 कोल्ड स्टोरेज इकाइयाँ और 1,000 कृषि उपज व पशुधन बाज़ार समितियाँ इनसे जे ड़ी गई हैं।

दूर संवेदी कक्षः कार्यालय में स्थापित दूर संवेदी कक्ष (आरएससी) ने वित्तीय वर्ष 2022 में 277 वाटरशेड परियोजनाओं को नाबार्ड भुवन पोर्टल से जोड़ा है. इसे मिलाकर अब कुल 901 परियोजनाएँ इस पोर्टल पर हैं। जियोटैग की गई आस्तियों की कुल संख्या अब 60,932 हो गई है जबकि आर.एस.सी ने 23 नए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन संचालित किए जिनमें दूर संवेदी और भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया गया।

मूल्यांकन अध्ययन संचालित किए जिनमें दूर संवेदी और भौगोलिक सूचना प्रणाली का 6.0 स्प्रिंगशेड विकास कार्यक्रमः वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान, पहाड़ी राज्यों में 31 नई स्प्रिंगशेड–आधारित वाटरशेड परियोजनाएं मंजूर की गईं। इसे मिलाकर अब तक 15 राज्यो में कुल 113 परियोजनाएँ मंजूर की जा चुकी हैं. नाबार्ड कार्यान्वयन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के प्रशिक्षण और क्षमता–निर्माण पर विशेष ध्यान देकर इन प्रयासों में और अधिक तेजी लाएगा।

- जीवा के माध्यम से कृषि–पारिस्थितिकीय परिवर्तन–एक नई पहल

जीवा (संस्कृत में जिसका अर्थ है 'जीवनशक्ति') बड़े पैमाने पर वाटरशेड और वाडी परियोजनाओं की निरंतर सफलता सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक और व्यापक बदलाव वाली कृषि–पारिस्थितिकी पद्धति में अग्रणी है।

प्राकृतिक खेती के मूल उद्देश्यों के साथ, जीवा का लक्ष्य फसल प्रगाली का विविधीकरण, मवेशियों व पेड़ों के प्रति समेकित दृष्टि, जैविक प्रक्रियाओं की पुनः बहाली, प्राकृतिक विधियों से कीट नियंत्रण और मिट्टी की नमी व आरिश के पानी का प्रभावी प्रबंधन करना है. यह कार्यक्रम 2023 के खरीफ सीजन से 11 राज्यों में 25 प्रायोगिक परियोजनाओं के रूप में संचालित किया जाएगा. धीरे–धीरे इसे बड़े स्तर पर सभी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजनाओं में लागू किया जाएगा.

3. अवनत मिट्टी का पुनः पोषण

अवनत हो चुकी मिट्टी के पुनः पोषण और उसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए नाबार्ड 2017 से केएफडब्ल्यू के साथ साझेदारी कर रहा है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ समुदाय जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अरक्षित हैं. तीन चरणों वाली परियोजना के पहले चरण के बाद भूमिगत जल में 6–30 फीट की वृद्धि हुई; 102 श्रम–दिवस प्रति वर्ष का रोज़गार बढ़ा; अंतर–फसलें, मिश्रित फसलें, अज़ोला की खेती और एसआरआई पद्धति आदि अपनाने में वृद्धि हुई; मूंगफली, धान और अरहर की उपज बढ़ी; और खाद्य सुरक्षा व पोषण में सुधार हुआ।

4. जनजातीय परिवारों के लिए आजीविका के प्रयास

जनजातीय विकास के बिना ग्रामीण विकास पूरा नहीं हो सकता. जनजातीय विकास निधि (टीडीएफ़)" से अब तक 5.8 लाख खेती–आधारित जनजातीय परिवार लाभान्वित हुए हैं; देश के 28 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में 898 परियोजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों के लिए 5.5 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में वाडी विकसित की गई हैं। इस कार्यक्रम के तहत 2.8 करोड़ से अधिक पेड़ (50 पौधे प्रति वाडी) लगाए गए हैं। अनुमान है कि उन पेड़ों के पूर्ण विकसित होने पर प्रति वर्ष 6.1 लाख टन कार्बन डाइ ऑक्साइड अवशोषित की जाएगी. नाबार्ड ने 499 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ भागीदारी करते हुए जारी और नई परेयोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2022 तक संचयी रूप से ₹2541.1 करोड़ मंजूर (₹1,802.2 करोड़ संवितरित) किए हैं। इनमें से, ₹162.9 करोड़ की वचनबद्धता के साथ 63 नई परियोजनाएँ वित्त वर्ष 2022 में मंजूर की गई हैं और ₹114.3 करोड़ संवितरित किए गए हैं। इन परियोजनाओं से 0.24 लाख परिवार लाभान्वित होंगे।

5. संधारणीय पौष्टिक आहार– कदन्न की खेती

जलवायु परिवर्तन अनुकूल फसलों के रूप में गेहूँ और चावल जैसे अन्य अनाजों की तुलना में सीमांत उपन परिस्थितियों (सूखे क्षेत्रों) में कदन्न अच्छी उपज देते हैं और उनमें उच्च पोषण तत्व होते हैं." कदन्नों के उत्पादन में भारत विश्व का अग्रणी देश है. राजस्थान में कदन्नों की सर्वाधिक उपजा होती है तत्पश्चात इस क्रम में महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं. ये अनाज प्रोटीन, रेशे, खनिज लवण, आयरन व कैल्शियम के प्रभावी स्रोत होने के साथ साथ ग्लूटन फ्री हैं। और इनका ग्लिसेमिक इंडेक्स कम होता है।

नाबार्ड अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके न केवल नाबार्ड से सहायता प्राप्त वाटरशेड व वाडी परियोजनाओं में कदन्नों के संवर्धन का प्रस्ताव करता है बल्कि कदन्नों पर आधारित एफपीओ के माध्यम से भी उत्पाद नवोन्मेष और व्यावहारिक विकास मॉडल को बड़े पैमाने भर लागू करने का प्रस्ताव करता है. कदन्न की खेती लाभप्रद है, यह प्रमाणित हो चुका है।

6. संधारणीय कृषि क्षेत्र का संवर्धन

2022 में कृशि क्षेत्र में संवर्धन

नाबार्ड कृषि आजीविका संबंधी जटिल चुनौतियों का संधारणीय समाधान खोजने के उद्देश्य से कृषि नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी अंतरण और किसानों की क्षमता निर्माण के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध कराता है इन गतिविधियों में शामिल हैः उत्पादकता सुधार, एकत्रण, नवोन्मेष, बाज़ार से जुड़ाव, अनुसंधान संस्थानों द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रसार, नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी का प्रायोगिक कार्यान्वयन, मूल्य श्रृंखला विकास, प्राकृतिक कृषि प्रणाली, हाई–टैक कृषि, कृषि में इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (आईओटी) आदि।

परिचय दौरों के माध्यम से किसान क्लबों के कौशल–आधारित प्रशिक्षण को बढ़ावा देना ताकि प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु किसानों की क्षमता निर्माण की जा सके।

ग्राम स्तरीय किसान संस्थाओं के गठन, प्रशिक्षण और क्षमता–निर्माण के लिए कार्यक्रमों और कृषि उत्पादोंध्मशीनरी के प्रदर्शन और नवोन्मेषी कृषि प्रथाओं के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित संगोष्ठियोंध्कार्यशालाओंध् सम्मेलनों आदि के लिए वित्तीय सहायता की।

नाबार्ड ने कृषि क्षेत्र संबर्धन निधि के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के (डीपीआर) माध्यम से मूल्य श्रृंखला प्रबंधन, आईओटी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी आदि के लिए वित्त वर्ष 2023 में ₹30 करोड़ का लक्ष्य रखा है। इस निधि से प्रायोगिक परियोजनाओं का विस्तार किया जाएगा ताकि असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाणा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण युवाओं को कृषि उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. इसके तहत प्रासंगिक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विचार–गोष्ठियों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि के लिए सहायता प्रदान करने और निर्यातोन्मुख राज्यों में कृषि निर्यात सुविधा केंद्रों के संवर्धन की भी योजना है.

7 निष्कर्ष

विकास के लिए समर्पित एक शीर्ष वित्तीय संस्थान के रूप में नाबार्ड पीपुल, प्लैनेट और प्रॉफिट की ट्रिपल बॉटम एप्रोच पर संधारणीय ग्रामीण समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर है. प्रमुख जलवायु निधियों की राष्ट्रीय कार्यान्वयन संस्था और प्रत्यक्ष पहुँच संस्था के रूप में नाबार्ड जलवायु परिवर्तन कार्यों में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हमारे कार्यों, निधियों और कार्यक्रमों के माध्यम से किए गए हमारे आर्थिक, सामाजिक, और पर्यावरणीय निवेश संधारणीय विकास के अधिकांश लक्ष्यों, यथा गरीबी उन्मूलन, भुखमरी निवारण, जलवायु कार्य, लैंगिक समानता, आर्थिक विषमता कम करना, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं आदि की प्राप्ति में सहायक हैं। पर्यावरण की शुद्धता और लाभप्रदता में संतुलन कायम करना और प्रकृति के साथ संघर्ष स्थान पर सामंजस्यपूर्ण सह–अस्तित्व स्थापित करना दोहरी चुनौती है।

नाबार्ड जलवायु अनुकूल कृषि–पारिस्थितिकीय आजीविकाओं और संधारणीय कृषि प्रणालियों के विकास के लिए नई प्रौद्योगिकी के प्रचलन और प्राथमिकता–निर्धारण में परिवर्तन के साथ जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यों, अनुकूलन, और शमन में ग्रामीण भारत की समग्र भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा।

REFERENCES

1. www.ipcc-ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_FinalDraft_FullReport.pdf.

2. आईपीसीसी (2021), 'समरी ऑफ़ पॉलिसीमेकर्स' इन क्लाइमेट चेंज 2021: द फ़िजिकल साइंस बेसिस, व वर्किंग ग्रुप टू द सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ़ द इन्टरगवन्मैटल पैनल ऑन क्लाइमेंट चेंज http.www.ipocch/report/ar6/wg1/downloadds/report/IPCC_ WGI_SPMpdf.AR6.

3. .पर्यावरण, जंगल और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार (2021), भारतः संयुक्तराष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन की तीसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट https.www.unfcccint/sites/default/files/resource/INDIA&þ20BUR3_20-02-2021_High.pdf.

4. अश्वनी कुमार और अन्य (2018), 'मिलेट्सः ए सॉल्यूशन टू अग्रेरियन एंड न्यूट्रिशनल चैलेंजेज़', ऐग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, वाल्यूम 7, आर्टिकल नं. 31, बायोमेड सेंट्रल लि., स्प्रिंगर नेचर. https.www//doi-org/10-1186/ $40066&018_0183&&3.

5. भारत सरकार (2018), राजपत्र अधिसूचनाः असाधारण सं. 133 (13 अप्रैल 2018), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार.

6. https//www.egazette-nic-in/ WriteReadData/2018/184777.pdf.

7. भारत सरकार (2022), केंद्रीय बजट (विव 2023), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

8. https://www.nabard.org/auth/writereaddata/tender/0607222123 study-on-rural-haats-and-marts-in-jharkhand.pd

9. https://www.ibef.org/blogs/growth-opportunities-for-thefood processing-industry-in-india.

10. भारतीय रिज़र्व बैंक (2012), 'ब्रिक्स डिजिट ल वित्तीय समावेशन रिपोर्ट, भारत 2021', मबुई, ब्रिक्सडिजिटल7330275एबीएफ़0सी419 बीB581897डीएफ़2सी131 सीए. पीडीएफ़ (rbi.org.in).